राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना

स्वतंत्रता के समय देश की आबादी लगभग ४०० मिलियन थी तथा खाद्यान्न की अत्यन्त कमी थी । उस समय देश की सिंचाई क्षमता केवल २० मिलियन हैक्टेयर थी । स्वतंत्रता के बाद सतही तथा भू जल दोनों के उपयोग तथा विकास के लिये सिंचाई के व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। इससे हरित क्रांति आई जिससे हमारा देश खाद्यान्नों की कमी से खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आ गया । इन व्यापक प्रयासों से वर्ष १९७९ तक देश का कुल सिंचाई क्षेत्र बढ़कर ५७ मिलियन हैक्टेयर हो गया, इसमें उच्च पैदावार देने वाली क़िस्मों तथा खादों का अधिक प्रयोग अहम है । इसी दौरान देश की खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता में १२५ मिलियन टन से १३० मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई । फिर भी खाद्यान्न उत्पादन की दर आबादी की वृद्धि दर के मुकाबले उस के मात्र बराबर हो पाई।

कृषि तथा मनुष्य की जिन्दगी में जल का महत्वपूर्ण योगदान है अतः जल का ईष्टतम उपयोग आवश्यक है। देश के जल संसाधनों के दोहन के उद्देश्य से, १९७२ में डा. के. एल. राव, तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने नदियों को आपस में जोड़ ने का विचार गंगा को कावेरी नदी से जोड़ ने वाले प्रस्ताव द्वारा प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् १९७७ में कैप्टन दस्तूर ने हिमालय, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के चारों तरफ नहर माला बनाना प्रस्तावित किया । यद्यपि इन प्रस्तावों को समाज के सभी वर्गों से अच्छी प्रतिक्रियायें मिली परन्तु इन प्रस्तावों को तकनीकी और आर्थिक तौर पर क्रियान्वयन के लिये संम्भाव्य नहीं समझा गया ।

जल संसाधन विकास में लगे कई लोगों द्वारा दर्शाई गई सतत रुचि ने अंतरबेसिन जल अंतरण प्रस्तावों का और अधिक विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग ने १९८० में जल संसाधन विकास के

लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने तथा उपलब्ध जल संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का अंतरबेसिन अंतरण करने पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक हिमालय नदी विकास तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास शामिल है।

हिमालय नदी विकास

हिमालय नदी विकास में भारत, नेपाल तथा भूटान में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों पर भण्डारण जलाशयों का निर्माण करने तथा गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अतिरिक्त प्रवाह को पश्चिम में पथांतरण करने के उद्देश्य से नदियों के अन्तर्योजी तंत्र निर्माण और ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों को गंगा से तथा गंगा को महानदी से जोड़ ने पर जोर दिया गया है।

प्रायद्वीपीय नदी विकास

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को चार प्रमुख भागों में बांटा गया हैः

- **महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना तथा इन बेसिनों में संभावित स्थानों पर जलाशयों का निर्माण:** यह नदी तंत्रों को आपस में जोड़ ने की सबसे बड़ी योजना है जिसमें महानदी तथा गोदावरी के अतिरिक्त जल को कृष्णा तथा कावेरी नदियों के द्वारा दक्षिण में जल आवश्यकता वाले क्षेत्रों को अन्तरित करने का विचार है।

- **मुंबई के उत्तर में तथा तापी के दक्षिण में पश्चिमोवर्ती प्रवाही नदियों को आपस में जोड़ना:** इस योजना में इन धाराओं पर यथा संभावित संख्या में ईष्टतम जलाशयों के निर्माण तथा उन्हें आपस में जोड़ कर पर्याप्त प्रमात्रा में जल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है जिससे कि उन क्षेत्रों में जल अन्तरित किया जा सके जहां अतिरिक्त जल की आवश्यकता है। इस योजना में जल आपूर्ति नहर को मुंबई महा नगरीय क्षेत्रों में ले जाने तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध करवाने का भी प्रबंध है।

- **केन-चंबल नदियों को आपस में जोड़ना:** इस योजना में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के लिए एक जल-ग्रिड तथा अन्तः संयोजी नहर जिसमें यथा संभव संख्या में जलाशय हों, का प्रावधान है।

- **अन्य पश्चिमोवर्ती प्रवाही नदियों का पथांतरण:** "पश्चिमी घाटों" के पश्चिमी ओर भारी मात्रा में वर्षा से असंख्य धाराएं आती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। केरल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा कुछ जल पूर्व में स्थित सूखा-प्रभावित क्षेत्रों को अंतरण करने हेतु एक अन्तः संयोजी नहर तंत्र के निर्माण की योजना बनाई जा सकती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में भण्डारण जलाशय भी हों।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल अंतरण अधिकांशत ग्रेविटी के द्वारा है, लिफ्ट कम से कम रखी गई है जो १२० मीटर तक ही सीमित है तथा बेसिन की निकट भविष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचे हुये अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण करने की योजना है ।